सहयोगी संघवाद

प्रदोष कुमार

भारतीय संघवाद को ए एच बिर्च एवं ग्रेनविले ऑस्टिन जैसे विद्वानों ने सहयोगी संघवाद के रूप में विवेचन किया। जिसमें केंद्रीय सरकार के शक्तिशाली होते हुए भी राज्य सरकार अपने अपने क्षेत्र में कमजोर ना हो। पारस्परिक अंतर निर्भरता की यह प्रणाली आज के दौर में संघवाद की सबसे बड़ी अनिवार्यता है। ग्रेनविले ऑस्टिन के अनुसार भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद है जिसमें केंद्रीय सरकार प्रबल है लेकिन उसका परिणाम यह नहीं है कि प्रांतीय सरकार कमजोर होकर केंद्रीय राजनीति के प्रशासनिक अभिकरण मात्र बने रहे।

सहयोगात्मक संघवाद का अभिप्राय यह है कि हमारा संविधान केंद्र एवं राज्यों के परस्पर सहयोग पर अधिक बल देता है ।भारत के संविधान निर्माताओं ने एक ऐसी संघ प्रणाली की कल्पना की थी। जो सहयोग एवं समन्वय पर आधारित हो सहकारी संघवाद सामान्य एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य प्रशासनिक सहयोग की पद्धति है। सहकारी संघवाद में राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार शासन व्यवस्था की स्वैच्छिक परिपूरक अंग समझी जाती है। जिनकी शक्तियों का प्रयोग संपूर्ण राज्य के सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करना होता है।

विगत दशकों में भारत में संघवाद के स्वरूप का विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होता है कि भारत में सहकारी संघवाद का ढांचा विकसित हुआ है विश्व की अन्य प्रणालियों की भांति भारत में संवैधानिक दृष्टि कौन से ही सहयोग की संस्थाओं को विकसित किया गया है शासन के परिचालन के दौरान ऐसी संस्थाओं एवं कार्यक्रम कार्यक्रम के नियमों का विकास हुआ जिससे केंद्र एवं राज्यों के मध्य संयोग की प्रवृत्ति का निरंतर विकास हुआ भारत में सहकारी संघवाद को विकसित करने में कुछ व्यवस्थाओं का योग रहा जैसे योजना आयोग जो वर्तमान में नीति

Scanned with CamScanner

आयोग के रूप में स्थापित हुआ राष्ट्रीय विकास परिषद वित्त आयोग की भूमिका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्षेत्रीय परिषदों परिषद अंतर राज्य परिषद एकल न्यायिक व्यवस्था अखिल भारतीय सेवाएं इत्यादि

सहयोगी संघवाद की अपरिहार्यता

इस प्रकार भारतीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत एवं व्यवहार में सहयोग एवं समन्वय के ऐसे सूत्र मौजूद हैं जो केंद्र एवं राज्यों को मिलकर सहयोगी संवाद का प्रतिमान विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं।

केंद्रीय कृत संघवाद एवं एकात्मक संघवाद के योग्य स्थान पर 1989 से 2009 के मध्य आम चुनाव के परिणाम के अनुसार संघ व्यवस्था का एक तीसरा प्रतिमान सामने उभर कर आया वह प्रतिमान सौदेबाजी वाला प्रतिमान रहा अल्फिया सरकारों के दौर में राज्यों के क्षेत्रीय दलों में सत्ता में बने रहने के समर्थन की एवज में केंद्र राज्यों के बीच सौदेबाजी की प्रवृत्ति सामने आई राज्यों के क्षेत्रीय दलों ने केंद्र से अपने लिए भागीदारी मनमाफिक मंत्रालय राज्यों के लिए विशेष पैकेज आदि मांगों से सरकार पर दबाव बनाए रखा।

अतीत में केंद्र एवं राज्यों में 44 वर्षों तक एक दल (**कॉन्ग्रेस**) के एकाधिकार के दौरान मुख्यमंत्रियों के चयन राज्य विधान सभा के चुनावों में प्रत्याशियों का चयन राज्य सरकार को बनाने गिराने का वीटो आदि दलीय आलाकमान का नियंत्रण निर्देशन से संघीय ढांचे में केंद्र का एक पक्षीय निर्णय इतिहास की घटना हो चला है। केंद्र के शासन की बागडोर अकेले राजनीतिक दल के पास नहीं बल्कि घटक दलों के सम्मेलन से बने गठबंधन ओं के हाथ में होती थी है।

16वीं लोकसभा चुनाव के पश्चात केंद्र से सत्तारूढ़ दल की अपेक्षाकृत सुदृढ़ स्थिति के बावजूद राज्यों में गठबंधन सरकारों की स्थिति क्षेत्रीय दलों का महत्व राज्यों के प्रतिनिधि सदन के रूप में राज्यसभा की भूमिका, न्यायिक पुनरावलोकन अतीत में, राज्यपालों की पक्षपात की भूमिका पर न्यायिक टिप्पणियां राज्यों के गठबंधन

Scanned with CamScanner

सरकारें एवं मीडिया के माध्यम से लोकमत के व्यक्ति ऐसे कारक हैं। जो किसी भी रूप में संघीय ढांचे एवं संघीय प्रवृत्ति को प्रभावित करने की अनुमति नहीं देती है। अपनी विस्तृत भूमिका के कारण निर्णायक बन चुके 1950 से स्थापित योजना आयोग जिसे **आर्थिक मंत्रिमंडल** या **सुपर कैबिनेट** कहा जाता था तथा केंद्र राज्य का पक्ष मजबूत करने के लिए संबंधों में केंद्र का प्रभारी होने के लिए जिम्मेदार माना जाता है को समाप्त कर राज्यों को ज्यादा सहभागिता के अवसर देने वाली अधिक संघीय नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को स्थापना की घोषणा एवं 5 जनवरी 2015 को इसका गठन किया जा चुका है।

राष्ट्र की आंतरिक राजनीतिक सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों एवं अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के परिपेक्ष में राजनीतिक क्षेत्र में आम सहमति तालमेल समन्वय के सूत्रों की अहमियत है ।यह तत्व तथ्य संघवाद के संबंध में भी मान्य है ।राज्यपाल की मर्यादित एवं विवेक संगत भूमिका केंद्र राज्य प्रशासनिक समायोजन के उपाय वित्तीय संसाधनों के न्याय पूर्ण आवंटन एवं केंद्र राज्य संबंधों में तनाव निवारण हेतु दी गई सरकारिया आयोग एवं पूंछी आयोग सहित अन्य सुधारवादी अनुशंसा पर प्रतिबद्धता से कार्य कर सहयोगात्मक संघवाद को स्थापित करने के नियोजित प्रयास करने होंगे। नवगठित नीति आयोग अंतर राज्य समितियां, क्षेत्रीय परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, मुख्य मंत्रियों एवं अन्य मंत्रियों के सम्मेलन आदि ऐसे अनेक माध्यम है जो इस सहयोग की सद्भाव संस्कृति को साकार रूप दे सकते हैं। निश्चय ही अब संघवाद में सबका साथ सबका विकास के सूत्रों का अनुपालन होगा।

Scanned with CamScanner